

सम्पादकीय

साइडलेफेक्ट गुटबाजी के रा

जस्थान कांग्रेस में सबकछु ठीक नहीं चल रहा है। प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तल्ली एक बार पिर सामने आ गई है। पायलट के खिलाफ गहलोत का हालिया आक्रमक बयान इस बात का सबूत है। आलाकमान ने कई बार इसे ठीक करने की कोशिश की लेकिन हालत जस की तस है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बीते दिनों कांग्रेस नेता सचिन पायलट के खिलाफ दिया गया आक्रमक बयान न तो अचानक आया है और वही इसे अप्रत्याशित माना जा सकता है। इसकी टाइमिंग जरूर कांग्रेस आलाकमान के लिए परेशानी पैदा करने वाली है, लेकिन इसके पीछे पार्टी में पढ़े चलने वाली गतिविधियां हैं। पायलट और गहलोत दोनों के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर रस्साकरी के चलते पार्टी में इतनी बड़ी उठापटकें हो चुकी हैं कि अब उसमें किसी तहक का रहस्य नहीं रहा।

आधिकार्य की बात कुछ ही सकती है तो यही कि दोनों गुटों में दूसरों की हृद तक जान वाली कड़वाहट और आलाकमान की ओर से इस विवाद को समय रहते होने की कोशिशों के बावजूद समस्या जस की तस है। जहाँ पायलट को यह जायदा शिकायत हो सकती है कि कथित तौर पर आलाकमान का बांबंगर आशासन मिलने के बाद भी सीएम पद से उनकी दूरी कम होने का नाम नहीं ले रही, वहीं गहलोत की यह असंका भी निराधार नहीं है कि मोंक मिलते ही पायलट कांग्रेस नेतृत्व के संरक्षण से उनकी कुसी छीन सकते हैं। अब जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश करने वाली है, तब दो दिन पहले गुर्जर नेता विजय सिंह बैसला ने पायलट को यहीं मुख्यमंत्री बनाने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर राजस्थान में यात्रा का विरोध होगा। हालांकि इसके पहले भी पायलट के पश्च में दबाव बनाने की प्रत्यक्ष या पारेक्ष कोशिशें होती रही हैं, लेकिन बैसला की मांग के बाद वियाका गांधी के साथ पायलट भी भारत में शामिल हुए।

इसके पूछ हल्कों में माना गया कि संभवतः अब पार्टी में स्वरूप स्तर पर पायलट के पश्च में फैसला हो जायगा। ऐसे में गहलोत ने अपने आक्रमक बयान के जरिए अपने समर्थकों को को ही नहीं, विरोधियों को भी आगह कर दिया कि कहाँ किसी भी प्रतिवादी को खामोशी से स्वीकार नहीं करें। दाउरल राजस्थान का विवाद कांग्रेस नेतृत्व के लिए इधर कुआं, उधर खाई की स्थिति साबित हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान पार करने से पहले कोई भी फैसला उस पर विपरीत प्रभाव डालेगा। इसके अलावा अशोक गहलोत गुरजरात विधानसभा चुनावों के प्रभारी हैं। उस लिहाज से भी तत्काल उनके खिलाफ किया गया कि कोई फैसला ठीक नहीं होगा। गजस्थान विधानसभा चुनाव भी अगले साल ही होने हैं। ऐसे में अगर नेतृत्व परिवर्तन करना है तो उस लिहाज से भी दो बातों वापर आपको लिहाज से जारी रहती है। लिहाज अगर कुछ न किया जाए तो उसके भी अपने नुकसान हैं व्यापक पायलट एम पद से खत्ते ही किसी भी चीज पर सत्तु होगे इसके आसार नहीं दिख रहे। कुल मिलाकर राजस्थान विवाद कांग्रेस नेतृत्व के लिए ऐसी भूलभूलैया बन चुका है, जिससे निकलने का कोई रास्ता उस नजर नहीं आ रहा।

इसी दौर में हमें यह भी याद आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश 'रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' की ग्लोबल प्रेस फ्रीडम रेकिंग में 180 देशों के बीच 150वें नंबर पर पहले ही पहुंच चुका है। आज सरकार की आलोचना करने वालों को अक्सर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है।

मीडिया की दुनिया में कॉर्पोरेट हस्तियों का आना



श्याम माईथुर
विचार परिवर्तन
@jagrukjanta.net

दुनिया के तीसरे सबसे अमीर अदानी और करीब 134 अरब डॉलर की संपत्ति के मालिक गौतम अदानी ने एनडीटीवी चैनल में बड़ी हिस्पेदारी खीरीने की तैयारी कर ली है और अब वे देश के मीडिया को नसीहत देने की भूमिका में भी नजर आने लगे हैं। कुछ महीने पहले चुपके से एनडीटीवी के शेयर खारिद कर रहे अपने नियन्त्रण में लेने की कोशिश करने वाले गोपन अदानी के कारोबारी हितों में ऑटोलिया की कोयले की खदानों से लेकर भारत के व्यापतम बदायाह तक का शामिल है। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पक्का समर्थक माना जाता है जिसके पक्षी तहक को तो यहाँ तक कहना है कि मोंक सिलते ही यात्रा की जायदात नीतीयां अंबानी और अदानी जैसे कारोबारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही हैं।

अपने दम पर अबपति बने गौतम अदानी ने मुकेत अंबानी की पीछे छोड़ कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने का रुखा हासिल किया है। नरेंद्र मोदी की तरह ही अदानी भी गुरजरत से आत है और बीते सालों में उनके कारोबार का पहिया बहुत तेजी से घूम रहा है। एयरपोर्ट से लेकर अक्षय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी कारोबारी की पीछे छोड़ कर फैला रहा है। ग्लोबल उनके प्रतिवर्षीय रूप के लिए इन्वेस्टर्स के विशेषज्ञों ने अगस्त में चेतावनी दी थी कि इस समूह को 'जरूरत से ज्यादा फायदा उठाने' के मोंक दिये जा रहे हैं।

अपने दम पर अबपति बने गौतम अदानी ने एनडीटीवी का पक्का

समर्थक माना जाता है

और वियाकी दलों का

तो यहाँ तक कहना है

कि मोदी सरकार की

ज्यादातर नीतियाँ

अंबानी और अदानी

जैसे कारोबारियों के

हितों को ध्यान में रखते

हुए बनाई जा रही हैं।

इसी साल अगस्त में अदानी एक कंपनी ने बताया कि उसने चैनल मैनेजमेंट की इच्छा के विरुद्ध अप्रत्यक्ष रूप से एनडीटीवी के 29 फीसदी शेयर खरीद लिये हैं और इसने पर चेतावनी दी थी कि इस समूह को 'जरूरत से ज्यादा फायदा उठाने' के मोंक दिये जा रहे हैं।

अदानी जैसे अबपति कारोबारी के हितों का ध्यान भी अपने एनडीटीवी का पक्का

समर्थक माना जाता है

और वियाकी दलों का

तो यहाँ तक कहना है

कि मोदी सरकार की

ज्यादातर नीतियाँ

अंबानी और अदानी

जैसे कारोबारियों के

हितों को ध्यान में रखते

हुए बनाई जा रही हैं।

इसी साल अगस्त में अदानी एक कंपनी ने बताया कि उसने चैनल मैनेजमेंट की इच्छा के विरुद्ध अप्रत्यक्ष रूप से एनडीटीवी के 29 फीसदी शेयर खरीद लिये हैं और इसने पर चेतावनी दी थी कि इस समूह को 'जरूरत से ज्यादा फायदा उठाने' के मोंक दिये जा रहे हैं।

अदानी जैसे अबपति कारोबारी के हितों का ध्यान भी अपने एनडीटीवी का पक्का

समर्थक माना जाता है

और वियाकी दलों का

तो यहाँ तक कहना है

कि मोदी सरकार की

ज्यादातर नीतियाँ

अंबानी और अदानी

जैसे कारोबारियों के

हितों को ध्यान में रखते

हुए बनाई जा रही हैं।

अपने दम पर अबपति बने गौतम अदानी ने एनडीटीवी का पक्का

समर्थक माना जाता है

और वियाकी दलों का

तो यहाँ तक कहना है

कि मोदी सरकार की

ज्यादातर नीतियाँ

अंबानी और अदानी

जैसे कारोबारियों के

हितों को ध्यान में रखते

हुए बनाई जा रही हैं।

अपने दम पर अबपति बने गौतम अदानी ने एनडीटीवी का पक्का

समर्थक माना जाता है

और वियाकी दलों का

तो यहाँ तक कहना है

कि मोदी सरकार की

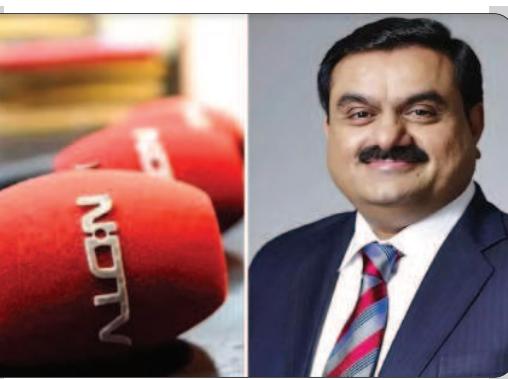
ज्यादातर नीतियाँ

अंबानी और अदानी

जैसे कारोबारियों के

हितों को ध्यान में रखते

हुए बनाई जा रही हैं।



जाने वाले टीवी चैनलों की बोहिसब भौद में थोड़ा अलग दिखता है, जो सरकार के आलोचकों को अपनी बात खबरों के लिए मंच देने के साथ ही सरकार की नीतियों के बारे में लगातार रिपो

